*ऋण- मांग पर बैंकरों के रुख - महामारी के बाद सुधार**

हरिद्वार यादव और सुप्रिया मजूमदार द्वारा

बैंक ऋण सर्वेक्षण, प्रमुख क्षेत्रों में निकट अवधि में ऋण की मांग, ऋण की शर्तों और उनके दृष्टिकोण पर बैंकों के रुख को बयां करता है जो वास्तविक ऋण वृद्धि के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है। यह आलेख महामारी के दौरान भारत में बैंकरों की भावनाओं के विकास का अध्ययन करता है। भले ही महामारी के दौरान, विशेष रूप से पहली और दूसरी लहर (क्रमशः अप्रैल-जून 2020 और अप्रैल-जून 2021) के समय, ऋण की शर्तों पर बैंकरों की भावना काफी प्रभावित हुई थी, इसके बाद इसमें तेजी से सुधार हुआ। विनिर्माण क्षेत्र में ऋण वृद्धि और उधारकर्ताओं की धारणाओं के साथ उधारदाताओं की भावना भी महत्वपूर्ण रूप से साथ-साथ चलती है।

भूमिका

बैंकों के प्रभुत्व वाली भारत जैसी अर्थव्यवस्था में नीति निर्माण के लिए ऋण मांग दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण इनपुट है। बैंक ऋण, अन्य बातों के साथ-साथ समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण, चलनिधि की स्थिति, उधारकर्ताओं की साख, संबंधित क्षेत्र से जुड़ी अनिश्चितता, जोखिम प्रीमियम सहित अपेक्षित रिटर्न, पोर्टफोलियो मिश्रण और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं जैसे कई कारकों पर निर्भर होता है। इनमें से कई प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं और इसलिए समर्पित बैंक ऋण सर्वेक्षण (बीएलएस)[1] के माध्यम से एकत्र की गई ऋण मांग तथा नियमों और शर्तों पर बैंकरों की धारणा, आमतौर पर बैंक ऋण पर जानकारी का पूरक होती है। बीएलएस धनात्मक रूप से ऋण बाजार की स्थितियों पर ऋणदाताओं का दृष्टिकोण प्रदान करता है, विशेष रूप से ऋण की मांग पर बदलती आर्थिक या वित्तीय स्थितियों के प्रभाव और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बैंकों द्वारा निर्धारित ऋण के नियम और शर्तों पर।

कोविड-19 संकट के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने फर्मों और हाउसहोल्ड को समर्थन देने के लिए कई तरह के ऋण उपाय/ योजनाएं शुरू कीं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कई उपायों की घोषणा की, जैसे नीतिगत दर और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) उधार में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करना, नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं, राज्यों की उधार सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने जैसे कई अन्य उपाय किए हैं। इन नीतिगत उपायों ने अर्थव्यवस्था को रोजगार और खपत में तेजी से बदलाव लाने में मदद की, जिससे ऋण मांग में भी वृद्धि हुई।

नीति निर्माण में बैंक ऋण सर्वेक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका उपयोग अधिकांश केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ऋण मांग एवं नियमों और शर्तों पर ऐसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान रुख का पता लगाने के लिए किया गया था, जब विश्वसनीय डेटा में कमी थी। सर्वेक्षण ने महामारी के प्रभाव के मापन के साथ-साथ बैंकों द्वारा अपेक्षित सुधार प्रक्रिया के समय और गति के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान की। इस आलेख में, हम देखते हैं कि महामारी के दौरान एक-के-बाद-एक लहरों में बैंकरों की भावना कैसे विकसित हुई।

शेष आलेख को निम्नलिखित खंडों में संरचित किया गया है। खंड II सर्वेक्षण का नमूना ढांचा, प्रश्नावली और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करता है। खंड III 2019-22 के दौरान सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष प्रदान करता है। खंड IV आधिकारिक आंकड़ों और अन्य सर्वेक्षणों के साथ इसके संबंध पर चर्चा करता है और खंड V कोविड के बाद की सुधार प्रक्रिया पर बैंकों की धारणाओं को प्रस्तुत करता है। खंड VI आलेख का समापन करता है।

---

^ लेखक सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग से हैं।

* इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। सर्वेक्षण के आंकड़ों का नवीनतम चरण 8 फरवरी 2023 को बैंक की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21736) पर जारी किया गया था। पिछला आलेख, बैंक ऋण सर्वेक्षण पर पहला आलेख था जो इसकी पृष्ठभूमि, अंतरराष्ट्रीय अनुभव समय शृंखला डेटा और पद्धतिगत पहलुओं पर जानकारी प्रदान करते हुए आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2020 के अंक (https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?id=19963) में प्रकाशित किया गया था।

[1] इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ ऋण अधिकारियों के सर्वेक्षण या ऋण स्थिति सर्वेक्षण के रूप में भी जाना जाता है।

II. नमूना फ्रेम, प्रश्नावली और कार्य-पद्धति

रिज़र्व बैंक, दुनिया भर के अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए इसी तरह के सर्वेक्षणों के अनुरूप व्यापक रूप से बैंक ऋण सर्वेक्षण आयोजित करता है। यह सर्वेक्षण भविष्य की ऋण मांग पर वरिष्ठ ऋण अधिकारियों की प्रत्याशा के साथ-साथ इसके नियमों और शर्तों में समायोजन के अलावा, मौजूदा ऋण बाजार की स्थितियों पर प्रतिक्रिया भी मांगता है। इसमें शीर्ष 30 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का एक पैनल शामिल है, जिनका सभी एससीबी के कुल बकाया ऋण में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया ऋण के आधार पर बैंकिंग कारोबार/ विलय में फैक्टरिंग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए यह पैनल अद्यतन किया जाता है। लक्षित उत्तरदाता विभिन्न ऋण विभागों के प्रमुख या बैंकों में विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ ऋण अधिकारी हैं। जिस तिमाही के लिए मूल्यांकन किया जाना है, उस तिमाही के दौरान बैंकों को सर्वेक्षण प्रश्नावली ई-मेल की जाती है और आम तौर पर सर्वेक्षण का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है। बैंक स्वेच्छा से सर्वेक्षण में भाग लेते हैं और प्रतिक्रिया की दर आम तौर पर 90 प्रतिशत से अधिक होती है।

सर्वेक्षण दो तिमाहियों के लिए बैंकों के दृष्टिकोण को ट्रैक करता है - ऋण मांग का मूल्यांकन और मौजूदा तिमाही के लिए नियम और शर्तें जिसमें पिछली तिमाही की तुलना में सर्वेक्षण किया जाता है एवं वर्तमान तिमाही की तुलना में आगामी तिमाही के लिए अपेक्षाएं। प्रश्नावली में व्यापक आर्थिक क्षेत्रों, यथा कृषि, खनन और उत्खनन, विनिर्माण, सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर और खुदरा ऋणों के साथ-साथ "सभी क्षेत्रों" को कवर करने वाले 5-बिंदु पैमाने पर उत्तर के साथ गुणात्मक प्रश्न शामिल होते हैं। ऋण की मांग के मामले में, वर्तमान तिमाही में परिवर्तन और अगली तिमाही के लिए 5-बिंदु पैमाने (परिमाण को मापने का तरीका) (यथा पर्याप्त वृद्धि, मध्यम वृद्धि, समान (अपरिवर्तित), मध्यम कमी और पर्याप्त गिरावट) की अपेक्षाओं पर प्रतिक्रियाएं मांगी जाती हैं। इसी तरह, ऋण नियमों और शर्तों पर प्रतिक्रियाओं को भी 5-बिंदु पैमाने पर चिह्नित किया जाता है (यथा काफी सुलभता, थोड़ी सुलभता, समान (अपरिवर्तित), थोड़ी सख्ती, काफी सख्ती)। ऋण नियम और शर्तें एक स्वीकृत ऋण के लिए विशिष्ट होती हैं, जो कि ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच सहमत शर्तें होती हैं और ऋण अनुबंध में निर्धारित होती हैं। इसमें कीमत और कीमत से इतर, दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है और इसमें प्रासंगिक संदर्भ/ ब्याज दर, ऋण का आकार और अन्य ब्याजेतर प्रभार (जैसे, शुल्क, संपार्श्विक या गारंटी की आवश्यकता, ऋण प्रसंविदा, सहमत ऋण परिपक्वता) पर सहमत स्प्रेड शामिल है। ऋण शर्तें उधारकर्ता की विशेषताओं पर सशर्त हैं और बैंक के ऋण अनुमोदन मानदंड के साथ बदल भी सकती हैं।

सर्वेक्षण के माध्यम से 5-बिंदु पैमाने पर एकत्र की गई प्रतिक्रियाओं को 'निवल प्रतिक्रिया (नेट रिस्पांस)' (एनआर)[2] नामक एक एकल संख्या में संकलित किया जाता है, जिसे बैलेंस स्टेटिस्टिक (बीएस) स्कोर या नेट बैलेंस के रूप में भी जाना जाता है, जो धनात्मक और ऋणात्मक प्रतिक्रियाओं के अनुपात के बीच का भारित अंतर है। एनआर -100 से +100 तक के मान ले सकता है: एनआर के धनात्मक मान मापदंड/ क्षेत्र के लिए आशावाद का संकेत देते हैं (उदाहरण के लिए, बैंकों को ऋण की मांग में वृद्धि या ऋण के नियम और शर्तों में ढील की उम्मीद है), जबकि शून्य से नीचे का मान निराशावाद को दर्शाता है (उदाहरण के लिए, निम्न ऋण मांग या ऋण के नियमों और शर्तों को सख्त करने की आशंका)। इस प्रकार, निवल प्रतिक्रिया गुणात्मक प्रतिक्रियाओं को मापने में मदद करती है जो रूखों में परिवर्तन की दिशा दर्शाती है; हालाँकि, यह परिवर्तन के परिमाण का कड़ाई से अनुमान नहीं लगाता है।

III. प्रमुख सर्वेक्षण निष्कर्ष

2017 में शुरू हुए सर्वेक्षण ने फरवरी 2023 में अपने हालिया डेटा जारी करने के साथ अपना 22वां चरण पूरा किया। कोविड-19 की दो लहरों के दौरान, ऋण की मांग और उसके नियमों और शर्तों पर बैंकरों की धारणाओं के रुझान नीचे दिए गए हैं।

---

[2] निवल प्रतिक्रिया (NR) = {1*P2 + 0.5*P1 + 0*P0 + (-0.5)*P(-1) + (-1)*P(-2)}, जहां, P2 = का प्रतिशत बैंकों ने ऋण की मांग को 'पर्याप्त वृद्धि' या ऋण के नियमों और शर्तों को 'काफी सहजता' के रूप में रिपोर्ट किया, P1 = बैंकों का प्रतिशत 'मध्यम वृद्धि' के रूप में ऋण की मांग या 'कुछ हद तक आसान' के रूप में ऋण की शर्तें, P0 = का प्रतिशत ऋण की मांग या ऋण के नियमों और शर्तों को 'समान/ कोई बदलाव नहीं' रहने की सूचना देने वाले बैंक, P(-1) = ऋण की मांग को 'मध्यम कमी' के रूप में रिपोर्ट करने वाले बैंकों का प्रतिशत या ऋण के नियम और शर्तों को 'कुछ हद तक कड़ा' और P(- 2) = ऋण मांग को 'पर्याप्त कमी' या ऋण नियमों और शर्तों को 'काफी सख्त' के रूप में रिपोर्ट करने वाले बैंकों का प्रतिशत।

III.1 ऋण मांग की शर्तें

(i) कोविड-19 की पहली लहर

कोविड-19 की पहली लहर से पहले 2019-20 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी-मार्च 2020) के दौरान, बैंकों ने सभी क्षेत्रों के लिए ऋण मांग पर कम आशावाद का संकेत दिया था (चार्ट 1)। जनवरी-मार्च 2020 के लिए सामान्य सर्वेक्षण भारत में 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन लागू होने से बहुत पहले किया गया था और इस तरह, बैंकों ने अर्थव्यवस्था में संकुचन का पहले से अनुमान नहीं लगाया था क्योंकि वे बाद में देखी गई महामारी की गंभीर और अप्रत्याशित प्रकृति के पूर्ण प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सके।

2020-21 (अप्रैल-जून 2020) की पहली तिमाही के दौरान कोविड-19 की पहली लहर के परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में ऋण की मांग में काफी कमी आई थी, जिससे आकलन के मामले में भारतीय बैंकों के रुख में भारी गिरावट आई थी। मूल्यांकन की गई तिमाही में सभी क्षेत्रों के लिए एनआर धनात्मक थे (चार्ट 2, अनुबंध चार्ट ए 1-ए 6)। हालांकि, अपेक्षाओं के संदर्भ में यह काफी हद तक अप्रभावित रहा। 2020-21 की दूसरी तिमाही में बैंकरों ने सभी क्षेत्रों में ऋण मांग की त्वरित बहाली का आकलन किया। खनन और उत्खनन तथा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम आशावाद दर्ज किया गया, जबकि व्यक्तिगत ऋण खंड में अधिकतम बहाली देखी गई, जिसमें पहले सबसे तेज गिरावट देखी गई थी। बैंकों ने 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान ऋण मांग में निरंतर सुधार की भी उम्मीद की। इस प्रकार, जबकि आकलन ने महामारी की पहली लहर के

चार्ट 1: सभी क्षेत्रों के लिए ऋण की मांग

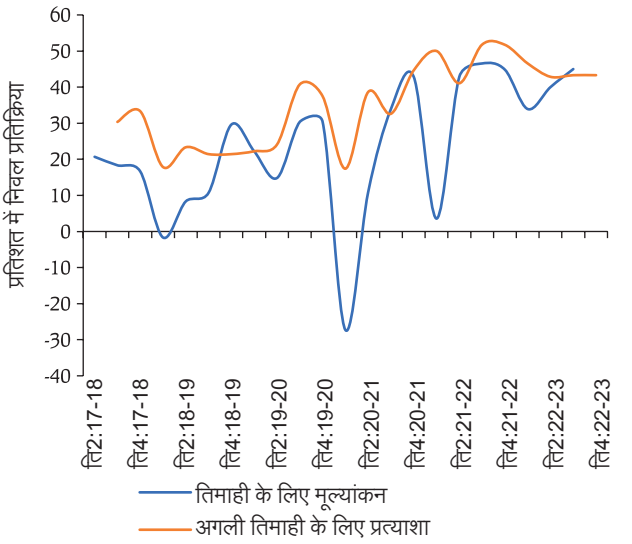

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 2: कोविड-19 की पहली लहर के दौरान क्षेत्र-वार ऋण मांग

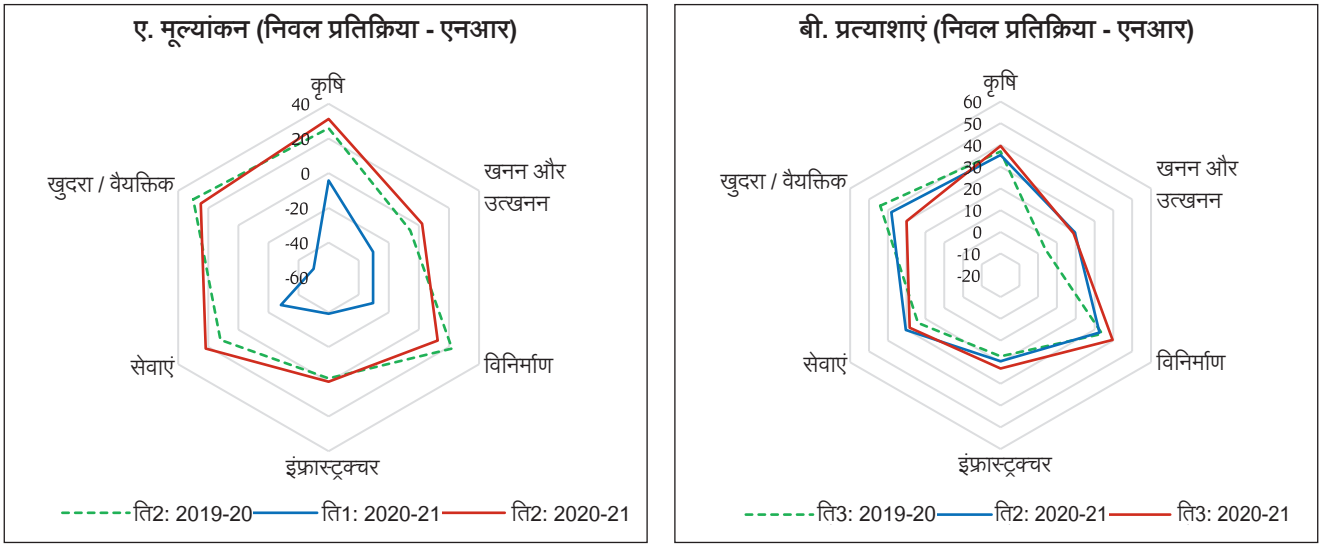

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 3: कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान क्षेत्र-वार ऋण मांग

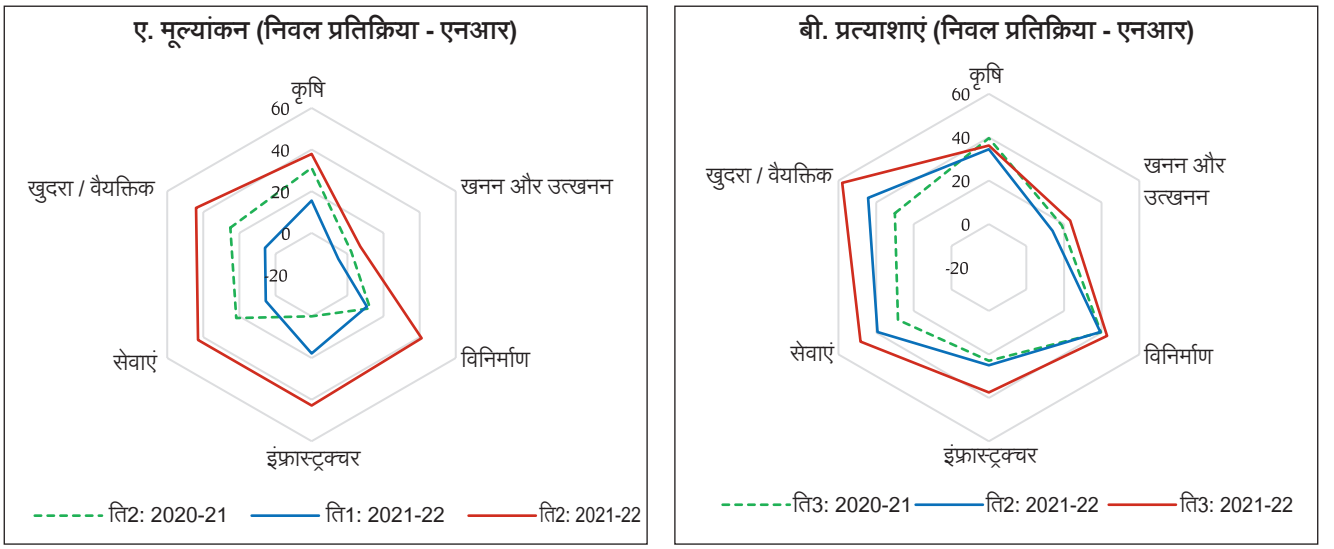

स्रोत: आरबीआई।

दौरान समग्र आर्थिक स्थितियों को प्रतिबिंबित किया, ऋण मांग की अपेक्षाएं अप्रभावित रहीं।

(ii) कोविड-19 की दूसरी लहर

2021-22 (अप्रैल-जून 2021) की पहली तिमाही में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, सभी क्षेत्रों में ऋण मांग पर बैंकों के रुख में काफी गिरावट आई (चार्ट 3, अनुबंध चार्ट ए 1-ए 6)। हालांकि, महामारी की पहली लहर की तुलना में गिरावट की सीमा बहुत कम थी क्योंकि खनन और उत्खनन को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए एनआर धनात्मक बने हुए थे। पहली लहर की तरह, अगली तिमाही (2021-22 की दूसरी तिमाही) में सभी क्षेत्रों में ऋण मांग पर बैंकरों के आकलन में तेजी से सुधार हुआ। तिमाही में वैयक्तिक ऋण खंड और सेवा क्षेत्र में तीव्र सुधार देखने को मिला। ऋण मांग पर बैंकरों की उम्मीदें 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए भी उत्साहित थीं और वास्तव में अधिकांश क्षेत्रों के लिए पिछली तिमाहियों की तुलना में अधिक थीं।

III.2 ऋण नियम और शर्तें

कोविड-19 महामारी के कारण महामारी की दोनों लहरों के दौरान विशेष रूप से मूल्यांकन के लिए भारतीय बैंकों के बीच ऋण नियमों और शर्तों के बारे में रुख में काफी गिरावट आई। हालांकि, प्रत्याशाएं काफी हद तक अप्रभावित रहीं (चार्ट 4)।

(i) कोविड-19 की पहली लहर

2020-21 की पहली तिमाही में कोविड-19 की पहली लहर में कृषि, खुदरा ऋण और विनिर्माण क्षेत्र के लिए नियम और शर्तों पर एनआर सकारात्मक थे, जो इन क्षेत्रों में आसान

चार्ट 4: 'सभी क्षेत्रों' के लिए ऋण के नियम और शर्तें

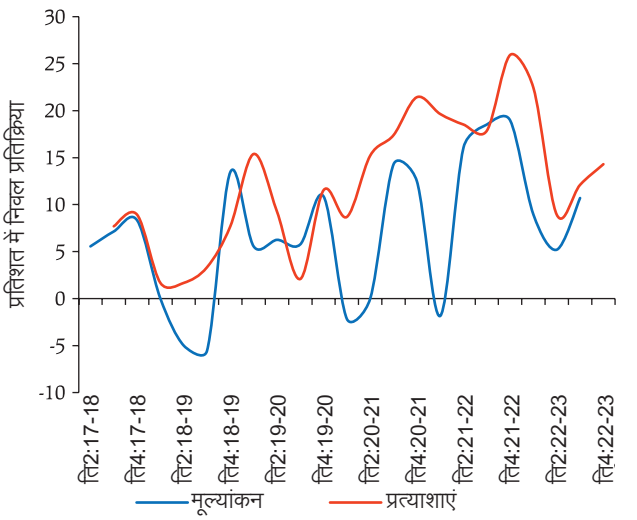

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट 5: कोविड-19 की पहली लहर के दौरान क्षेत्र-वार ऋण के नियम और शर्तें

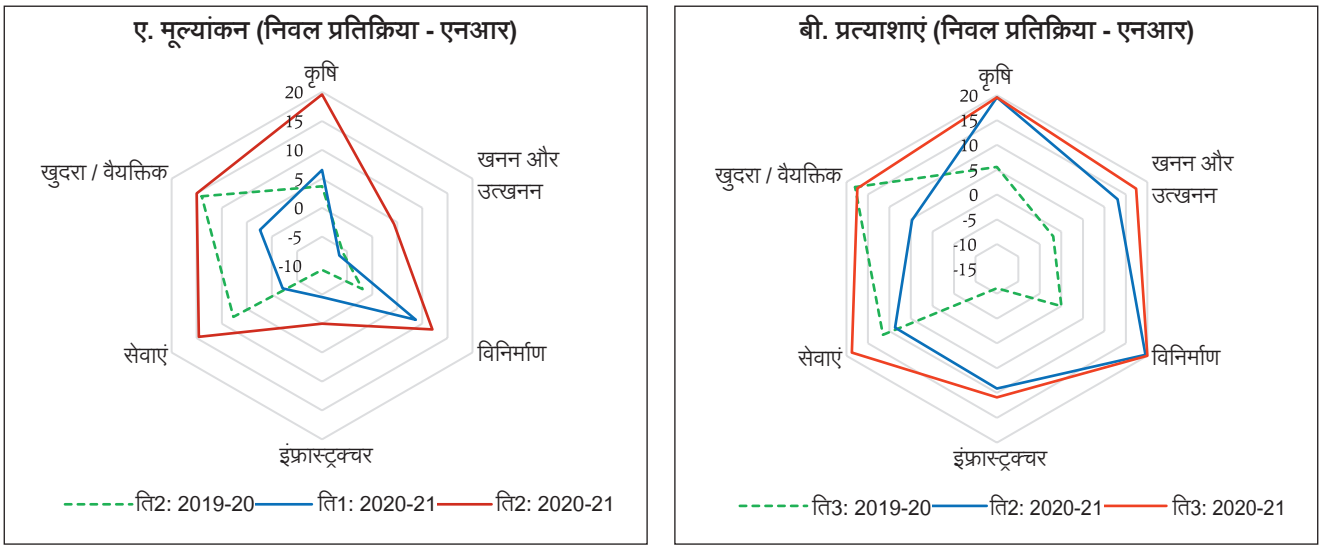

स्रोत: आरबीआई।

ऋण नियमों और शर्तों को दर्शाता है। हालांकि, अधिक बैंकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और खनन और उत्खनन क्षेत्र के लिए, ऋण शर्तों में कुछ सख्ती की सूचना दी। सभी क्षेत्रों के लिए ऋण नियमों और शर्तों पर रुख ने 2020-21 की दूसरी तिमाही में नरमी का संकेत दिया। बैंकरों ने 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान ऋण के नियमों और शर्तों में और ढील की उम्मीद की (चार्ट 5)।

(ii) कोविड-19 की दूसरी लहर

भले ही दूसरी लहर के दौरान ऋण शर्तों पर बैंकरों के रुख में गिरावट आई, जैसा कि सभी ऋण क्षेत्रों के लिए एनआर के मूल्य में गिरावट में परिलक्षित होता है, लेकिन महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह सकारात्मक रहा, जो पहली लहर की तुलना में आसान नियम और शर्तों का संकेत देता है (चार्ट 6)। इसके अलावा, सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए अगली

चार्ट 6: कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान क्षेत्र-वार ऋण के नियम और शर्तें

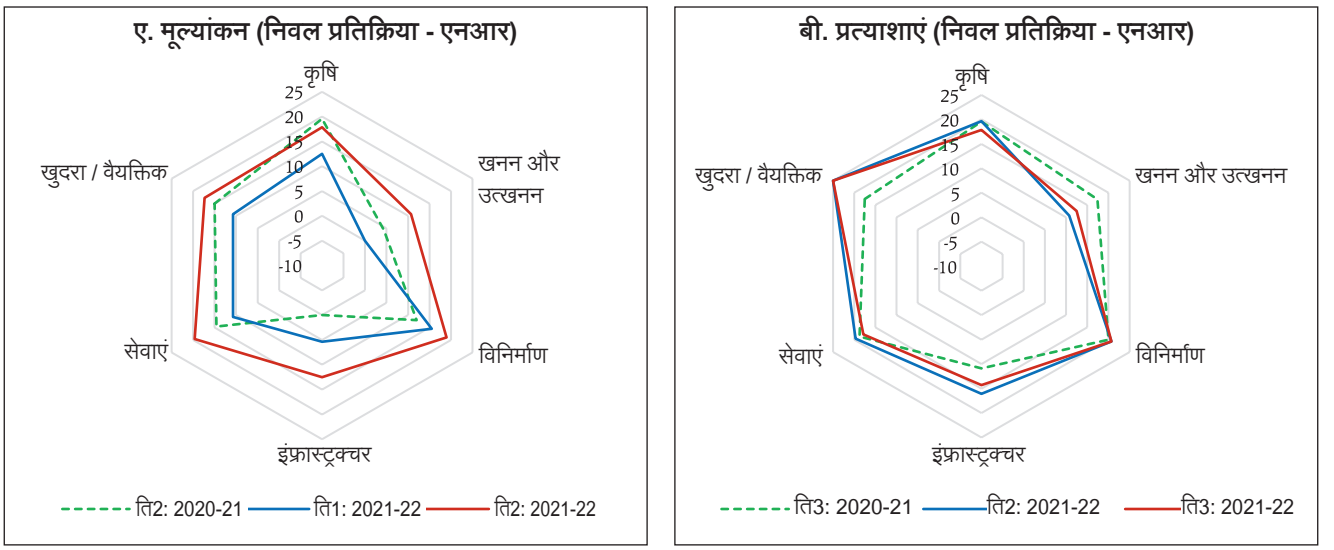

स्रोत: आरबीआई।

तिमाही 2021-22 की दूसरी तिमाही में बैंकों द्वारा ऋण नियमों और शर्तों संबंधी रुख में कमी दर्ज की गई।

IV. आधिकारिक सांख्यिकी और अन्य सर्वेक्षणों के साथ बीएलएस का संबंध

यह खंड वास्तविक ऋण के साथ-साथ अन्य सर्वेक्षणों के रुझानों के साथ सर्वेक्षण परिणामों की तुलना करता है ताकि यह समझा जा सके कि क्या इन सर्वेक्षणों से उपलब्ध जानकारी नीति निर्माताओं को प्रमुख जानकारी प्रदान कर सकती है।

IV.1 बैंक ऋण सर्वेक्षण और वास्तविक बैंक ऋण

शुद्ध प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में ऋण मांग में परिवर्तन का बैंकरों का आकलन एससीबी द्वारा दिए गए वास्तविक ऋण में वृद्धि को बारीकी से ट्रैक करता है। हालांकि, मूल्यांकन की तुलना में, उनकी प्रत्याशाएं आम तौर पर अधिक उत्साहित रही हैं (चार्ट 7)। मूल्यांकन के लिए एनआर और वास्तविक ऋण वृद्धि के बीच सहसंबंध गुणांक 0.49 है, जबकि यह प्रत्याशाओं और वास्तविक ऋण वृद्धि के लिए एनआर के बीच 0.23 है।

IV.2 विनिर्माण क्षेत्र - उधारकर्ताओं और उधारदाताओं द्वारा ऋण शर्तों का आकलन

बीएलएस ऋण की मांग और उसके नियमों और शर्तों के बारे में ऋणदाता के दृष्टिकोण (आपूर्ति पक्ष के दृष्टिकोण) को ग्रहण करता है, जबकि आरबीआई का त्रैमासिक औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण (आईओएस) [3] बैंकों और अन्य घरेलू स्रोतों से वित्त की उपलब्धता पर निर्माताओं के मांग पक्ष के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। आईओएस 3-पॉइंट स्केल (सुधार / खराब / कोई बदलाव नहीं) पर वित्त की उपलब्धता पर मूल्यांकन और अपेक्षाओं को एकत्र करता है और इसके परिणाम निवल प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। बीएलएस में बैंकरों द्वारा मूल्यांकन किए गए विनिर्माण क्षेत्र से ऋण मांग और आईओएस में निर्माता द्वारा मूल्यांकन किए गए बैंकों और अन्य स्रोतों से वित्त की उपलब्धता अध्ययन अवधि में समान दिशात्मक परिवर्तनों का संकेत देती है (चार्ट 8)।

चार्ट 7: 'सभी क्षेत्रों' के लिए बीएलएस ऋण की मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

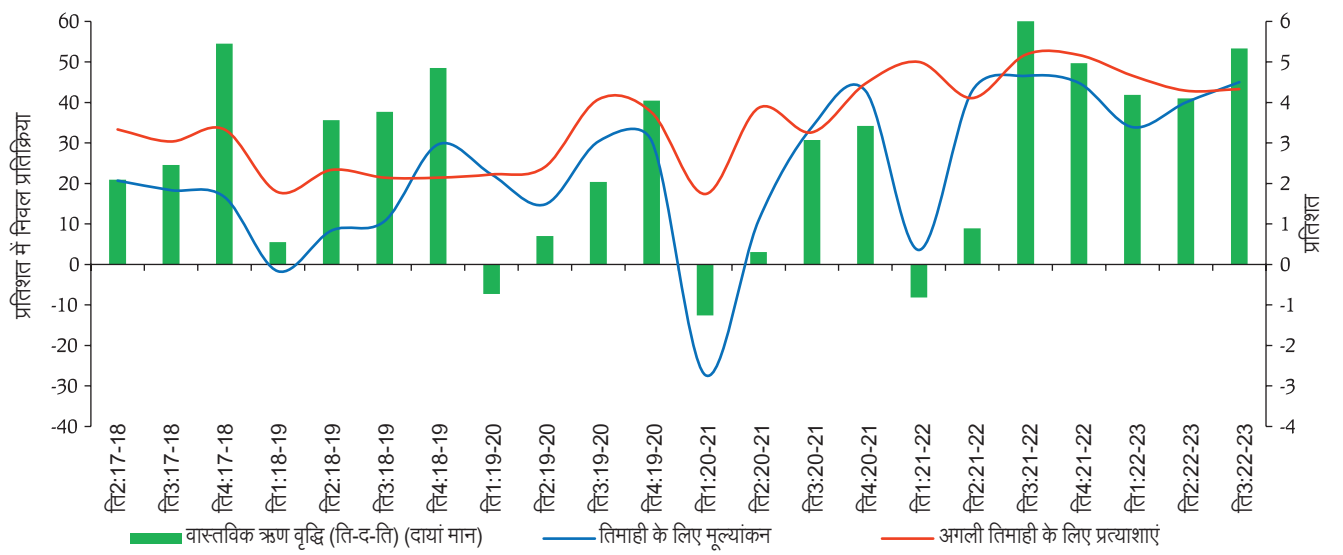

स्रोत: आरबीआई।

[3] आईओएस डेटा, आरबीआई की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21734) पर तिमाही आधार पर जारी किए जाते हैं, नवीनतम डेटा 8 फरवरी 2023 को जारी किया गया था)।

[4] आईओएस में विनिर्माताओं के बीच प्रचारित मापदंड हैं: 'वित्त की उपलब्धता (बैंकों और अन्य घरेलू स्रोतों यथा, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार आदि)', 'वित्त की उपलब्धता (आंतरिक संसाधनों से)' और 'वित्त की उपलब्धता (विदेशों से)'।

चार्ट 8: बीएलएस-विनिर्माण क्षेत्र की ऋण मांग और आईओएस - वित्त की उपलब्धता

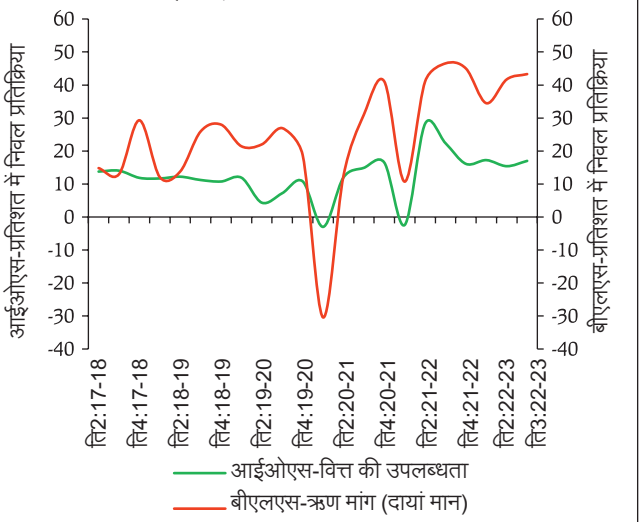

स्रोत: आरबीआई।

विनिर्माण क्षेत्र के लिए ऋण नियमों और शर्तों का बैंकरों का आकलन आम तौर पर वित्त की उपलब्धता पर निर्माताओं के रुख के अनुरूप होता है (चार्ट 9)। इन दोनों सर्वेक्षणों से उत्पन्न निवल प्रतिक्रिया के सह-संचलन से संकेत मिलता है कि ऋण अधिकारियों का आकलन काफी हद तक उद्योग की प्रत्याशाओं के अनुरूप है।

चार्ट 9: बीएलएस-विनिर्माण क्षेत्र के नियम और शर्तें एवं आईओएस - वित्त की उपलब्धता

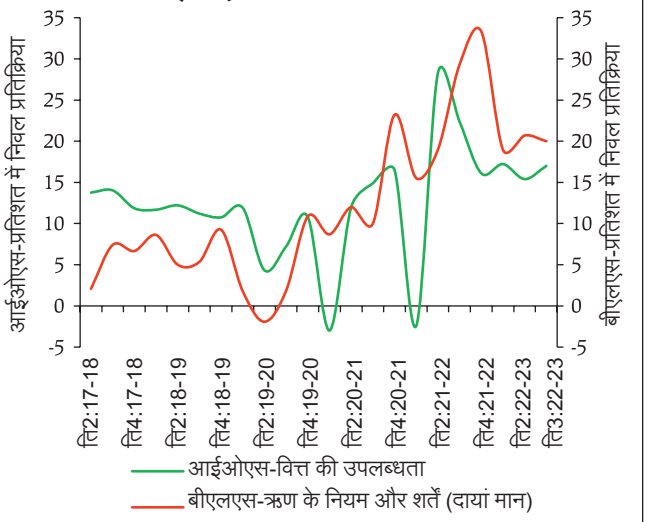

स्रोत: आरबीआई।

V. कोविड-19 के बाद के सुधार के संबंध में बैंकों की धारणा

V.1 देश व्यापी अनुभव[5]

चूंकि बैंक ऋण सर्वेक्षण मौद्रिक नीति निर्णयों का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने इन सर्वेक्षणों का उपयोग कोविड-19 प्रभाव पर बैंकों की भावनाओं का पता लगाने के लिए उपकरणों के रूप में किया। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व ने सर्वेक्षण के अप्रैल 2020 के दौर में बताया - "कई बैंकों ने मानकीकृत सर्वेक्षण प्रश्नों का उत्तर देने के अलावा कोरोना वायरस (कोविड -19) महामारी के बारे में लिखित टिप्पणियां भी प्रदान कीं। इन टिप्पणियों में, बैंकों ने बताया कि पहली तिमाही के लिए रिपोर्ट किए गए ऋण श्रेणियों में मानकों और मांग में बदलाव मार्च के अंत में हुआ क्योंकि कोविड-19 के तेजी से वैश्विक प्रसार के बारे में खबरें सामने आने पर आर्थिक दृष्टिकोण बदल गया। यूरो क्षेत्र के बैंक ऋण सर्वेक्षण के नतीजों से पता चला है कि 2020-21 और 2021-22 की पहली तिमाहियों में ऋण मांग और ऋण नियम और शर्तों पर रुख गर्त में पहुंच गए, जो भारत में कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के समान है। बड़े जापानी बैंकों में बैंक ऋण प्रथाओं पर बैंक ऑफ जापान के वरिष्ठ ऋण अधिकारी राय सर्वेक्षण ने यह भी दर्शाया कि कोविड-19 महामारी की विभिन्न लहरों के दौरान बैंकों के रुख निम्नतम स्तर पर पहुंच गए। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने क्रेडिट कंडीशन सर्वे में दर्शाया कि सुरक्षित और असुरक्षित ऋण मांग पर बैंकों की धारणा अगली तिमाहियों में पुनर्जीवित होने से पहले 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान गर्त में पहुंच गई।

V.2 भारतीय संदर्भ

2020-21 की पहली तिमाही के सर्वेक्षण चरण के बाद से, ऋण पर बैंकों के दृष्टिकोण और बाद की दो और तिमाहियों के लिए इसके नियमों और शर्तों का आकलन करने के लिए एक अलग ब्लॉक पेश किया गया था। इस प्रकार, प्रत्याशाओं पर डेटा कुल तीन तिमाहियों के लिए एकत्र किया गया था जो अनिश्चित समय के दौरान नीतिगत निर्णयों के लिए बेहद उपयोगी बन गया। इसके अलावा, लगातार सर्वेक्षण चरणों में उसी तिमाही के लिए प्रत्याशाओं को भी हासिल किया गया था, जिससे नीति निर्माताओं

[5] केंद्रीय बैंकों की संबंधित वेबसाइटें (संदर्भों में दी गई हैं)

को गतिशील रूप से विकसित महामारी और आर्थिक परिदृश्य के जवाब में प्रत्याशाओं में बदलाव का निरीक्षण करने में मदद मिली। इस अतिरिक्त ब्लॉक का उपयोग करते हुए, हम ऋण मांग और ऋण की शर्तों पर उम्मीदों को देखते हैं और देखते हैं कि कोविड रिकवरी के बाद उन्हें कैसे आकार दिया गया।

(i) ऋण मांग की स्थिति

भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेजों और उपायों ने महामारी की पहली दो लहरों के दौरान ऋण मांग पर बैंकों के रुख में सुधार को बढ़ावा दिया। हालांकि पहली लहर के बाद रुख मजबूत होने लगे, लेकिन दूसरी लहर के कारण ये फिर से कमजोर हो गए, हालांकि वे जल्दी से वापस आ गए (चार्ट 10)[6]। बैंकों के रुख एससीबी की वास्तविक ऋण वृद्धि के अनुरूप भी देखे गए। यह देखा गया है कि बैंकर दो और तीन तिमाही आगे की प्रत्याशाओं के संदर्भ में अधिक आशावादी होते हैं और एक तिमाही आगे की प्रत्याशाएं वास्तविक ऋण वृद्धि का अधिक बारीकी से पता लगाने में सक्षम थीं।

हाल की अवधि में हम देखते हैं कि बैंकर आने वाली तिमाहियों में सभी मुख्य क्षेत्रों में ऋण मांग के बारे में अत्यधिक आशावादी हैं, अर्थात्, 2022-23 की चौथी तिमाही से 2023-24 की दूसरी तिमाही जैसा कि उनके उच्च एनआर (अनुबंध चार्ट ए1-ए6) में परिलक्षित होता है।

(ii) ऋण नियम और शर्तें

ऋण नियमों और शर्तों के संदर्भ में, पहली लहर के दौरान गिरावट के बाद, प्रत्याशाओं ने ऋण नियमों और शर्तों को आसान बनाने का संकेत दिया। हालांकि, दूसरी लहर के कारण रुख फिर से नीचे आ गया, यद्यपि इसमें त्वरित सुधार हुआ। हाल की अवधि के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि बैंकर आगे चलकर ऋण के लिए आसान नियम और शर्तों की उम्मीद कर रहे हैं (चार्ट 11)।

चार्ट 10: विभिन्न चरणों में ऋण मांग का मूल्यांकन और प्रत्याशाएं

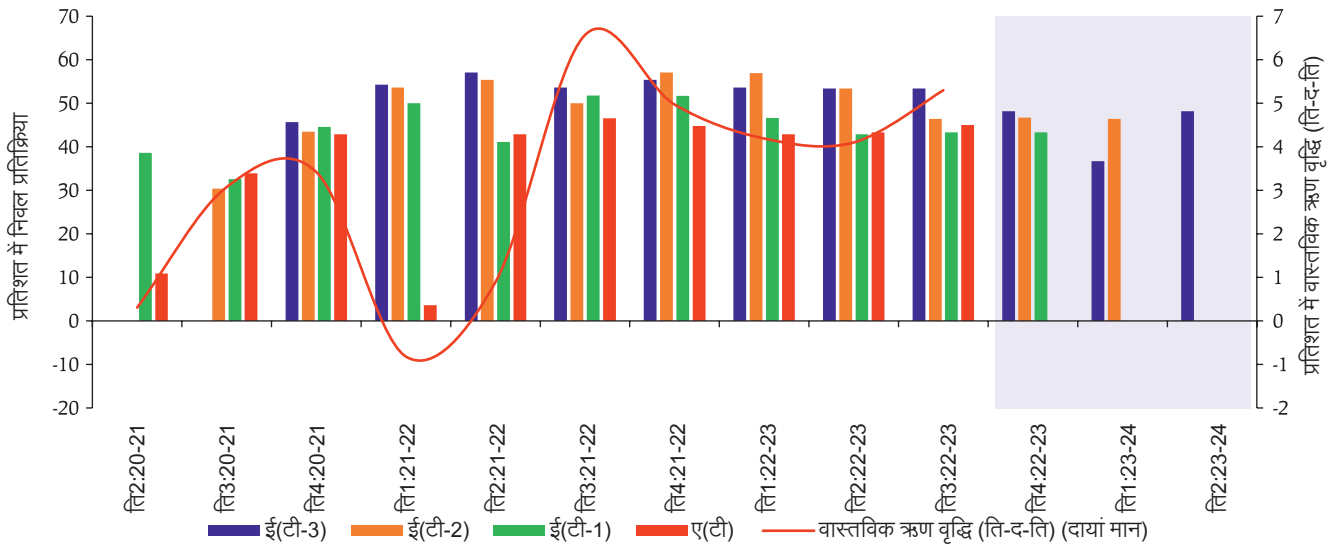

स्रोत: आरबीआई।

[6] ए(टी): मौजूदा तिमाही (टी), ई(टी-1)/ई(टी-2)/ई(टी-3) के लिए आकलन; तिमाही (टी) के लिए प्रत्याशाएं एक (-1) / दो (-2)/ तीन (-3) तिमाही पहले का पता लगाती है।

चार्ट 11: विभिन्न चरणों में नियम और शर्तों पर मूल्यांकन और प्रत्याशाएं

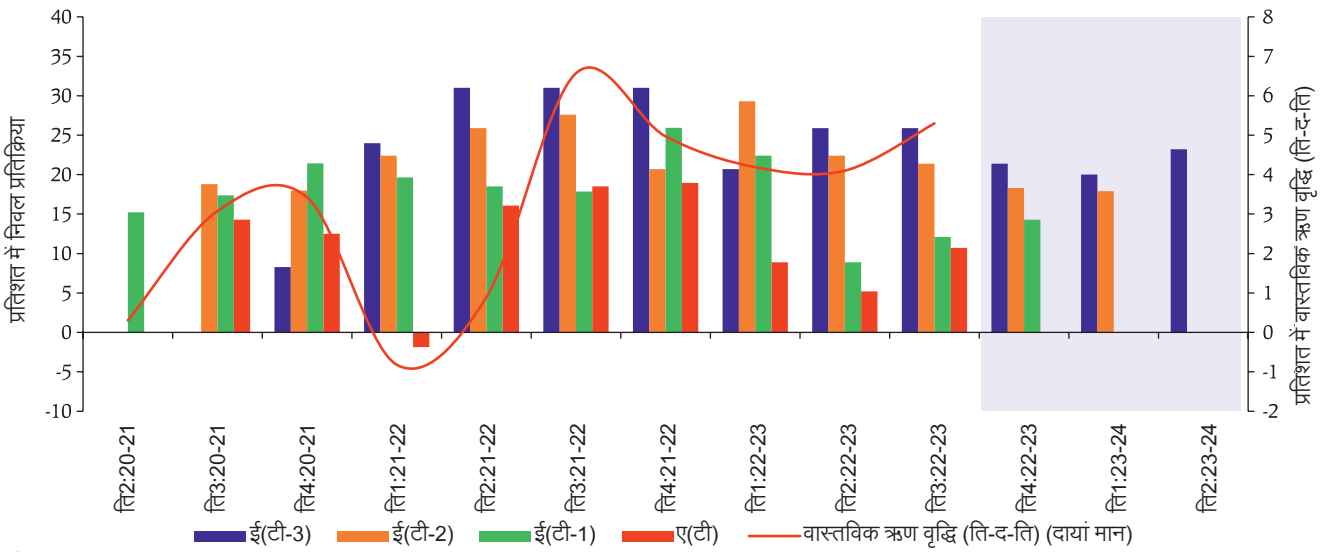

स्रोत: आरबीआई।

VI. निष्कर्ष

यह आलेख बैंक ऋण सर्वेक्षण के लगातार चरणों के परिणामों का अवलोकन करता है ताकि यह समझा जा सके कि महामारी की अवधि के दौरान विभिन्न आघातों पर रूखों ने कैसे प्रतिक्रिया दी। हम पाते हैं कि पहली और दूसरी लहर के दौरान उधार देने की स्थितियों के मूल्यांकन ने महामारी के प्रति निराशावादी तरीके से प्रतिक्रिया की। हालांकि, एक तिमाही के भीतर ऋण स्थितियों के मूल्यांकन में काफी सुधार हुआ है, जो दर्शाता है कि अनिश्चितता के दौरान नीतिगत उपाय विश्वास पैदा करने में प्रभावी थे। क्षेत्रों में, महामारी की दोनों लहरों के दौरान खुदरा/ वैयक्तिक ऋण पर दृष्टिकोण सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था, लेकिन उन्होंने मजबूत पकड़ दिखाते हुए तेजी से सुधार दर्ज किया।

बैंक ऋण सर्वेक्षण (बैंक लेंडिंग सर्वे) की जानकारी उचित सटीकता के साथ वास्तविक ऋण वृद्धि को ट्रैक करती है और बड़े बदलावों का पता लगाती है। इसलिए, यह नीति निर्माताओं के लिए ऋण बाजार में अंतर्निहित प्रवृत्तियों को मापने के लिए एक उपयोगी जरिया हो सकता है, क्योंकि सर्वेक्षण के परिणाम अग्रिम रूप से लगभग एक तिमाही पहले उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही, बीएलएस में उधारदाताओं की धारणा व्यापक रूप से औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण में उधारकर्ताओं की धारणाओं के साथ पुष्टि करती है, जो इंगित करती है कि आपूर्तिकर्ताओं का मूल्यांकन - ऋण शर्तों के मांग पक्ष के साथ समन्वयित है, जो फिर से इसकी उपयोगिता साबित करता है।

भविष्य में बैंकर आगामी तिमाहियों में ऋण मांग को लेकर सकारात्मक हैं। ऋण के लिए नियम और शर्तों पर प्रत्याशाएं भी क्रमिक तिमाहियों में सहजता की ओर इशारा करती हैं।

संदर्भ

Bank of England (2022), "Bank of England Credit Conditions Survey", Quarterly Bulletin, Q1. https://www.bankofengland.co.uk/credit-conditions-survey/2022/2022-q1

Bank of Japan, "Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices at Large Japanese Banks". https://www.boj.or.jp/en/statistics/dl/loan/loos/index.htm/#p01.

Berg, Jesper., Van Rixtel, Adrian A.R.J.M., Ferrando, Annalisa., de Bondt, Gabe and Scopel, Silvia., (2005), "The Bank Lending Survey for the Euro Area". ECB Occasional Paper No. 23, February 2005. https://ssrn.com/abstract=752072.

Board of Governors of the Federal reserve (2022), "Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices", July. https://www.federalreserve.gov/data/sloos.htm.

Cunningham, Thomas J., (2006), "The Predictive Power of the Senior Loan Officer Survey: Do Lending Officers Know Anything Special?", Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper, November.

European Central Bank (2022), "The Euro Area Bank Lending Survey - First Quarter of 2022", Q1. *https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/ecb.blssurvey2022q1~fd61911ffd.en.html.*

Faruqui, Umar, Paul Gilbert, and Wendy Kei., (2008), "Bank of Canada's Senior Loan Officer Survey", Bank of Canada Review, Autumn, https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/06/faruqui.pdf.

Filardo, Andrew J. and Siklos, Pierre L., (2020), "The cross-border credit channel and lending standards surveys", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol.67.

Köhler-Ulbrich, Petra., Hempell, Hannah S., Scopel, Silvia., (2016), "The euro area bank lending survey: Role, development and use in monetary policy preparation", European Central Bank Occasional Paper Series, No.179, September.

Reserve Bank of India, Database on Indian Economy, https://dbie.rbi.org.in.

Reserve Bank of India (2009), "Report of the Working Group on Surveys", Reserve Bank of India Bulletin, September.

Reserve Bank of India (2021), "Annual Report of the RBI for the Year 2020-21", May.

Reserve Bank of India (2022), "Annual Report of the RBI for the Year 2021-22", May.

अनुबंध

चार्ट ए1: 'कृषि' के लिए बीएलएस ऋण मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

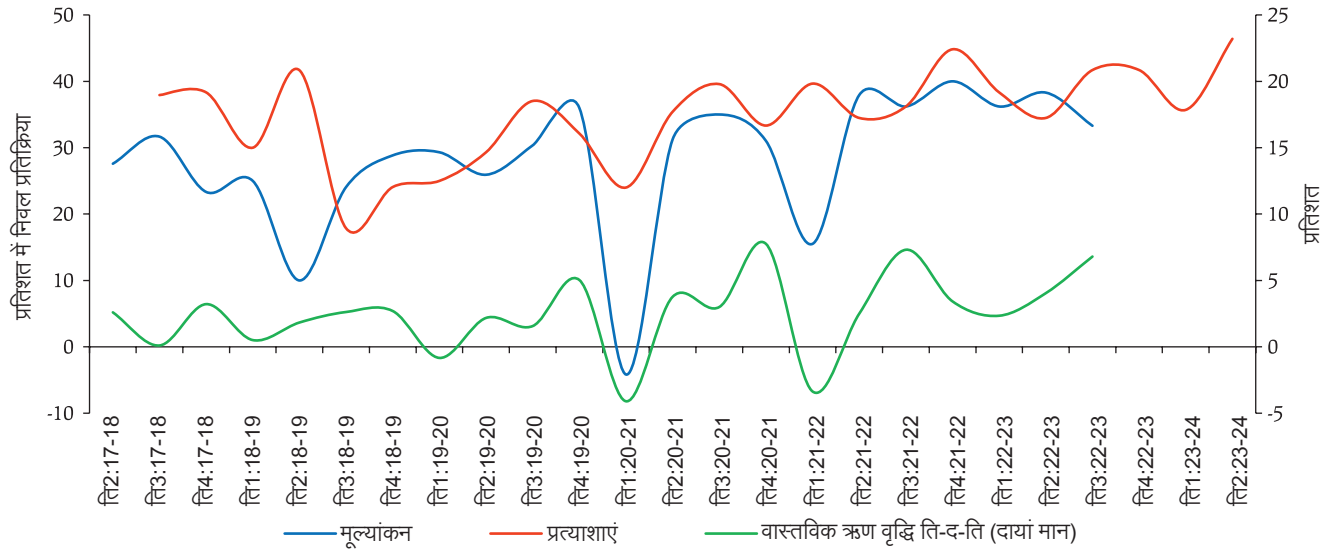

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट ए2: 'खनन और उत्खनन' के लिए बीएलएस ऋण मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

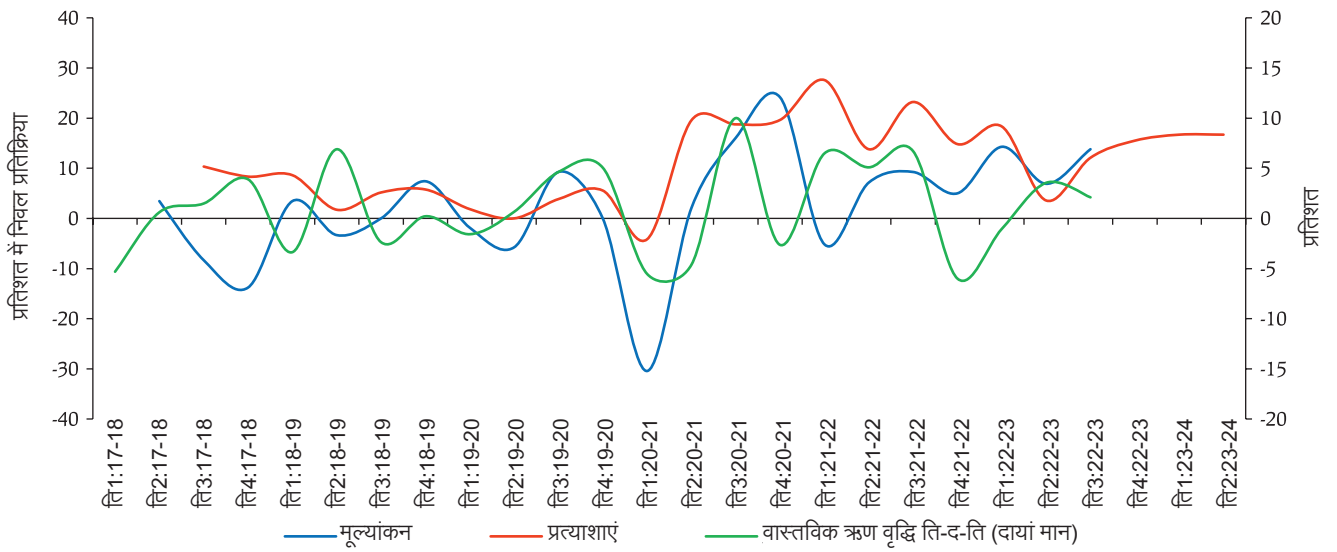

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट ए3: 'विनिर्माण' के लिए बीएलएस ऋण मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

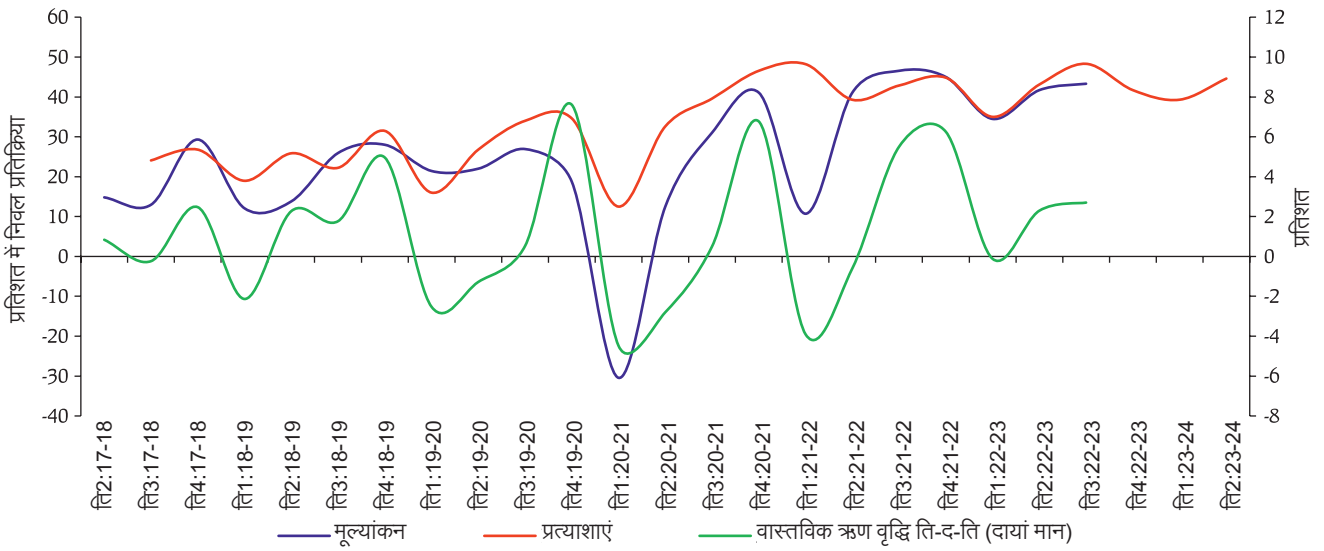

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट ए4: 'इंफ्रास्ट्रक्चर' के लिए बीएलएस ऋण मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

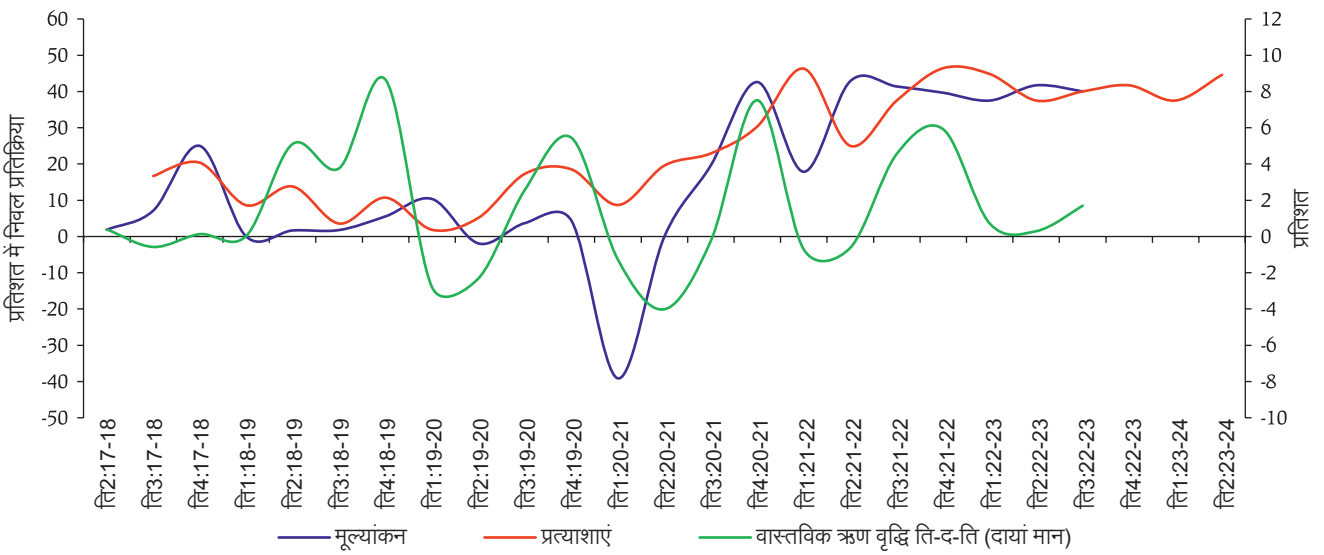

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट ए5: 'सेवाओं' के लिए बीएलएस ऋण मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

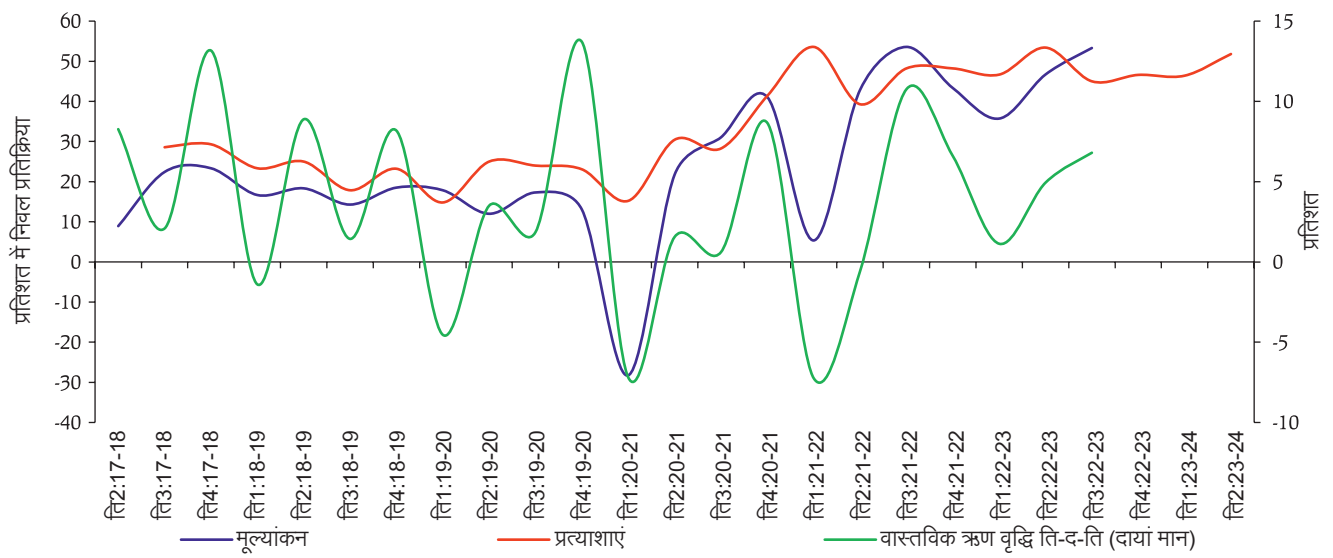

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट ए6: 'वैयक्तिक ऋण' के लिए बीएलएस ऋण मांग और वास्तविक ऋण वृद्धि

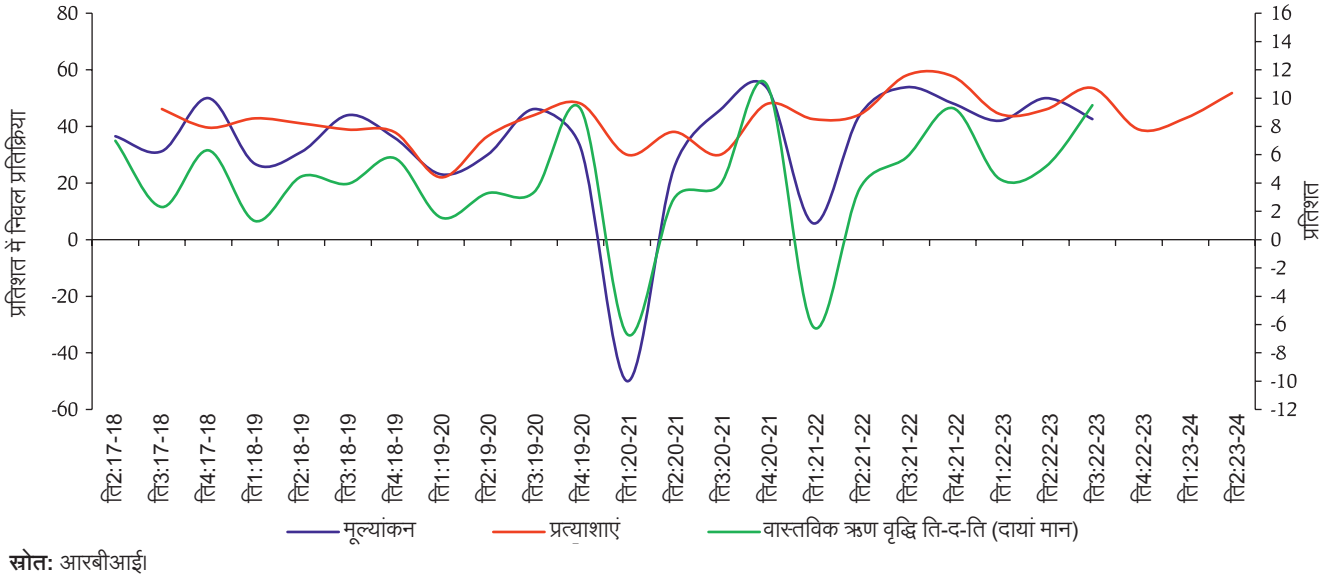

स्रोत: आरबीआई।